SHRI P. A. SANGMA: Sir, there is absolute need to improve productivity. I do admit that, but I have not had much of time to go into all aspects of the working of the Ministry. I am still trying to acquaint myself with the work. Increase in productivity will certainly receive priority on my agenda.

MR. CHAIRMAN: Next Question.

कोयल कारो जल-विद्युत परियोजना के निष्पादन में विलम्ब

*203. **श्री चतुरानन मिश्र :†**
श्री राम अवधेश सिंह :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 710 मेगावाट की महत्वपूर्ण कोयल कारो जल-विद्युत परियोजना में विलम्ब हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस परियोजना पर काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि कोयल कारो जल-विद्युत परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय जून, 1981 में लिया गया था परन्तु भूमि के अधिग्रहण के विरुद्ध स्थानीय लोगों के प्रतिरोध और स्थानीय लोगों को उनकी भूमि से बेदखल किए जाने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका । उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय लोगों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है और उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कर दिया है । परियोजना के संबंध में वन संबंधी स्वीकृति जुलाई, 1990 में प्राप्त हुई थी । परियोजना की लागत को अद्यतन कर दिया गया है और नए सिरे से निवेश संबंधी निर्णय हेतु कार्यवाही की जा रही है । परियोजना का निर्माण-कार्य लगभग 8 वर्ष में पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

†सभा में यह प्रश्न श्री चतुरानन मिश्र द्वारा पूछा गया ।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, जिस क्षेत्र में यह कोयल कारो प्रोजेक्ट है वह बिहार का आदिवासी क्षेत्र है और आप जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ और गरीब क्षेत्र है । अगर पन बिजली की व्यवस्था हो जाए तो उनकी स्थिति काफी अच्छी हो सकती है क्योंकि थर्मल पावर से जो बिजली बनती है उसकी कास्ट ज्यादा आती है । फिर भी केन्द्रीय सरकार ने यह योजना 1981 में शुरू की थी और आज 1991 हो गया । 10 वर्ष चले गए हैं लेकिन यह आरंभ नहीं हुई जो बहुत ही दुख का विषय है । हमारे पास सूचना है कि प्लानिंग कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया है । यह सूचना सही है या नहीं, यह मंत्री महोदय बताने की कृपा करें ।

उत्तर में आपने कहा है कि यह प्रोजेक्ट 8 साल में पूरा हो जाएगा । तो उस 8 साल में से पहला साल कब होगा, यह भी मंत्री महोदय बताएं ।

श्री सभापति : कब शुरू होगा और कब पूरा होगा ?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, मैं आदरणीय साथी को बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का टेक्नो-इकानामिक क्लियरेंस मिल चुका है । 1981 में यह योजना शुरू होने वाली थी तो स्थानीय लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और दो साल तक यह आंदोलन चलता रहा ।

श्री सभापति : उसमें चतुरानन जी तो शामिल थे ।

श्री कल्पनाथ राय : उस समय बिहार

की सरकार और वहां के विभिन्न दल के लोगों ने उस आंदोलन को रोकने में कोई मदद नहीं की । वे लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में 1984 से 1989 तक 5 साल यह मामला लटका रहा । इसके बाद भारत सरकार ने इसमें पहल की । इसके लिए पर्यावरण की स्वीकृति मिल चुकी है, वन संबंधी स्वीकृति मिल चुकी है, टेक्नो-इकानामिक क्लियरेंस हो चुकी है, प्लानिंग कमीशन से स्वीकृति मिल चुकी है।...

श्री सभापति : प्लानिंग कमीशन से क्लियरेंस हो गई है ?

श्री कल्पनाथ राय : अब यह 15 मई से पहले इनवेस्टमेंट बोर्ड के सामने विचाराधीन है । इसके बाद सी. सी. ई. ए. केबिनेट कमेटी में यह जाएगा ।

मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि बिहार में इस समय 44 परसेंट पिकिंग लोड शार्टेज है और 31 परसेंट इनर्जी शार्टेज है । इस पिकिंग लोड शार्टेज को सही नजर रखते हुए सरकार ने कोयल कारो जल-विद्युत योजना को स्वीकृति देने का निर्णय लिया है ।...

श्री रजनी रंजन साहू : पहले इनको धन्यवाद तो दीजिए.... (**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : बाकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन मैंने पूछा था कि यह कब शुरू होगी, 8 साल में से पहला साल कब शुरू होगा, धन्यवाद तो तब दूंगा । .... (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : इसी वर्ष में योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्री चतुरानन मिश्र : कार्यान्वयन शुरू होगा ?

श्री कल्पनाथ राय : हां, एक महीने के अंदर ।

श्री चतुरानन मिश्र : मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी तभी होगा । अभी तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और एक महीने के बाद यदि काम नहीं हुआ तो वापस ले लूंगा ।

श्री सभापति : दूसरा सवाल पूछ लीजिए ।

श्री दीपेन घोष : दूसरा सवाल एक महीने के बाद होगा ।

श्री यशवंत सिन्हा : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्योंकि कोयल कारो प्रोजेक्ट जो है यह टिपिकल उदाहरण है इस बात का कि हमारे यहां प्रोजेक्ट की गति या दुर्गति होती है । तो क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1981 में जब यह प्रोजेक्ट हम शुरू करने जा रहे थे उस समय इसकी लागत क्या थी और अभी इसका रिवाइज एस्टीमेट क्या है या होने जा रहा है ? उस रिवाइज एस्टीमेट में क्या हम लोगों ने 8 साल जो कम्पलीशन का पीरियड है उसको ध्यान में रखकर उस लागत को बढ़ाया था ? इसी का पार्ट-बी है कि उसका कास्ट बेनिफिट एनालिसिज 1981 में क्या किया गया था और अब उसका कास्ट बेनिफिट एनालिसिज क्या है ?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, जब 1981 में यह योजना स्वीकृत की गई थी तो उस समय मार्च में उस वक्त के प्राइस के अनुकूल 391 करोड़ रुपये इस योजना के लिए रखे थे । लेकिन आज इस योजना पर 1145 करोड़ रुपये खर्च होंगे । 710 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा ।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने पूछा है कि क्यों इतनी देर हुई । आप जानते हैं कि पर्यावरण विभाग ने बहुत समय लिया । वन विभाग बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में 8 वर्षों तक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में पत्राचार होता रहा । बिहार की सरकार ने इसमें

जितनी दिलचस्पी दिखानी चाहिए थी उतनी नहीं दिखाई । माननीय सदस्य जो बिहार के हैं उन लोगों को भी थोड़ी दिलचस्पी बिहार के विकास के काम में लगानी चाहिए तब ही यह काम पूरा हो सकेगा ।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Mr. Chairman, on behalf of the people of Bihar I would like to record our deep appreciation of the Minister's two observations (1) that he has firmly recognized that Bihar is a power starved State and (2) that he has announced a time-bound programme for the implementation of the Koel Karo project. But, at the same time, I would like to ask, is his enthusiasm shared by his colleagues in the Central Electricity Authority who are the policy-making body and his Ministry, because I suspect that unless cooperation of the entire range of establishment within his purview is with him, there are risks that all kinds of spokes will be put into that? Keeping that in view and appreciating his assertion that there is power shortage in Bihar, of a grave kind, will he, at a the same time, institute steps which will supplement the power supply, that is, more Centrally-sponsored thermal power projects on a time-bound basis, on a priority basis, located in Bihar, and (b) will the transmission, problems of Bihar he 1eken up on a priority basis under the new organization that he has set up?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी ने अपना एश्योरेंस दे दिया है । सभी पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिल चुकी है, वन संबंधी स्वीकृति मिल चुकी है, सारी स्वीकृतियां मिल चुकी हैं और केवल पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के पास अगले धर्सडे को यह जा रहा है फिर कैबिनेट में जायेगा । बिहार की शार्टेज को मद्देनजर रखते हुए इस कोयल कारो योजना को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है । जहां तक बिहार का सवाल है इस समय बिहार में प्लांट लोड फैक्टर 29 परसेंट है । ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लोड 23 परसेंट है । पूरे देश में सबसे ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर बिहार में है । इस दुर्गति के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है या नहीं ?

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर : आप क्या करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : मैं यह कहूंगा कि बिहार सरकार के पास 1300 मेगावाट इंस्टाल्ड कैपेसिटी है और वहां केवल 29 परसेंट प्लांट लोड फैक्टर है । इसके लिए बिहार सरकार ही जिम्मेदार है । जहां तक हमारी सरकार का सवाल है यह सैन्ट्रल सेक्टर में 710 मेगावाट बिजली की योजना को स्वीकृति देने का निर्णय ले लिया है । हमारे इस निर्णय से बिहार सरकार की स्थिति में सुधार होगा

श्री राज मोहन गांधी : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति टेहरी डेन प्रोजेक्ट को मिली है या नहीं और अगर मिली है तो कब मिली है और नहीं मिली है तो क्या पर्यावरण मंत्रालय ने कोई संदेह व्यक्त किये हैं तो वे क्या संदेह हैं ?

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बड़े विद्वान सदस्य हैं । इसके लिए उन्हें अलग से सवाल करना चाहिए ।

Development of Ajanta and Ellora

204. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: t

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to develop Ajanta and Ellora

tTlhe question was actually asked on the, floor of the House by Shri Vishwasrao Ramrao Patil.